

श्री आई० के० गुजराल : श्रीमन्, एक बात का ध्यान आनरेबिल मेम्बर रखें तो ठीक रहेगा, जैसा मैंने कहा, कि दिल्ली के अन्दर सेटिस्फेक्शन 43 परसेंट है, लेकिन दिल्ली के बाहर सेन्ट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिमों का सेटिस्फेक्शन इससे बहुत कम है, मसलन बम्बई में केवल 5 परसेंट है, कलकत्ते में करीब करीब इसी तरह का है। इसलिए इन जगहों के मुकाबले में दिल्ली की हालत बेहतर है, बाकी जगह हालत इससे बुरी है।

जहां तक शेड्यूल्ड कास्ट के भाइयों का सवाल है, हम लोग उस बारे में पूरा ध्यान रखते हैं और कुछ परसेंट क्वार्टर उनको देते भी हैं।

*216. [The questioner (Shri Bhola Prasad) was absent. For answer, vide cols 37-38 infra]

‘लाखों को दूध’ योजना

*217. श्री लाल आडवाणी :

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत :†

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में सस्ता दूध दिलाने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की समिति द्वारा तैयार की गई 193 करोड़ रुपये की “लाखों को दूध” नामक पंचवर्षीय परियोजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

MILK FOR MILLIONS" SCHEME

• 217. SHRI LAL K. ADVANI :
SHRIMATI LAKSHMI KUMARI
CHUNDAWAT :f Will the Minister of
AGRICULTURE be pleased to state :

(a) what are the detailed outlines of the

†The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Lakshmi Kumari Chundawat.

†[] English translation.

Five Year Project entitled "Milk for Millions" costing rupees 193 crores and prepared by the Committee of the United Nations Organisation for supplying cheap milk, in Delhi, Bombay Madras and Calcutta; and

(b) what is the reaction of Government in this regard ?]

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) पूछी गई जानकारी निश्चित रूप से परियोजना दुग्ध विपणन तथा डेरी विकास के सम्बन्ध में है जो साधारणतः आपरेशन फ्लड के नाम से प्रसिद्ध है और जो विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से भारत सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है। इस परियोजना की विस्तृत रूपरेखा देने वाला एक नोट सभा पटल पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट LXXX, अनुपत्र संख्या 26]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. SHER SINGH) : (a) and (b) The information sought is evidently in respect of the Project Milk Marketing and Dairy Development commonly known as Operation Flood being undertaken by Government of India in cooperation with the World Food Programme. A note giving the detailed outlines of the Project is laid on the Table of the Sabha (See Appendix LXXX_ Annexure No. 26)]

श्री बनारसी दास : श्रीमन्, यह सहायता जो वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन से मिलेगी और यह सारी इंडियन मिल्क कारपोरेशन को दी जाएगी, इंडियन मिल्क कारपोरेशन कीमत लेकर यह देगा, तो कीमतें कैसे इन बड़े बड़े शहरों में दूध की कम होंगी ?

प्रो० शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्किमड मिल्क पाउडर और बटर मिल्क मिलेगा और उसको लिक्विड मिल्क में कन्वर्ट करेंगे, वे प्राइस तो चार्ज करेंगे, मुफ्त नहीं देंगे, लेकिन कीमतें इससे ज्यादा बढ़ने की बात नहीं है, वाजिव कीमत ली जायेगी।

डा० जेड० ए० अहमद : यह कैसे कह सकते हैं कि कीमत बढ़ने की बात नहीं है।

†[] English translation.

श्री बनारसी दास : उन्होंने कहा है कि 42 करोड़ रुपए का पाउडर बड़ीदा के इंडियन मिल्क कारपोरेशन को दिया जायेगा और इंडियन मिल्क कारपोरेशन दिल्ली, बम्बई, मद्रास में जो मिल्क योजनाएं हैं उनको कीमत लेकर देगा। प्रश्न यह था कि सस्ता दूध किस तरह से उपलब्ध होगा। इस योजना से जो सहायता मिलेगी वह तो केवल एक प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए होगी जिससे दूध की सप्लाई बढ़े, लेकिन इससे कीमत कम होगी इसकी कोई योजना सरकार ने नहीं बतलाई।

प्रो० शेर सिंह : दूध की एवेलिबिलिटी जब ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा होगी तब उसका इन्डाइरेक्ट असर कीमतों पर पड़ सकता है।

*218. [The questioners (Sarvashri Sundar Mani Patel, Lokanath Misra, K. C. Panda and Chandra-mouli Jagarlamudi) were absent. For answer, vide cols. 38 infra]

*219. [The questioner (Shri Kalyan Roy) was absent. For answer, vide col. 39 infra]

♦220. [The questioner (Shri J. P. Tadav) was absent. For answer vide col. 40 infra]

*221. [The questioner (Shri Sitaram Kesri) was absent. For answer, vide col. 40 infra]

*222. [The questioner (Shri Togendra Sharma) was absent. For answer, vide col. 41 infra]

मध्य प्रदेश में चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति

*223. श्री जगदीश प्रसाद माथुर :†
श्री बी० के० सखलेचा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति अत्यन्त खराब है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश की कुछ मिलों ने अभी तक किसानों को

1970-71 और 1971-72 के लिये गन्ने का मूल्य अदा नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इन चीनी मिलों के सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

FINANCIAL POSITION OF SUGAR MILLS IN MADHYA PRADESH

* 223. SHRI JAGDISH PRASAD
MATHUR :† SHRI V. K.
SAKHALECHA :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the financial position of sugar mills in Madhya Pradesh is awfully bad;

(b) whether it is also a fact that some of the mills in Madhya Pradesh have not so far paid the price of Sugar-cane to the growers for the years 1970-71 and 1971-72 ; and

(c) if so, what steps Government propose to take in regard to these sugar mills ?]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. SHER SINGH) : (a) No Sir.

(b) There are practically no arrears on account of cane purchased during 1970-71 season. Even for 1971-72 only a small amount of about Rs. 1.30 lakhs remains to be paid, against the total cane price of about Rs. 154.0 lakhs for the cane purchased during this year.

(c) Revenue recovery certificates would be issued by the State Government, wherever

§ [कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) 1970-71 मौसम के दौरान खरीदे गए गन्ने की वस्तुतः कोई राशि बकाया नहीं है। 1971-72 के लिए भी केवल लगभग 1.30 लाख रुपये की थोड़ी-सी राशि का भुगतान करना शेष है। जबकि उक्त वर्ष में कुल लगभग 154.0 लाख रुपये का गन्ना खरीदा गया था।

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Jagdish Prasad Mathur.

†† English translation.

§† Hindi translation.

necessary.